ठाकुर बृजराजसिंह व अन्य

बनाम

ठाकुर लक्ष्मणसिंह व अन्य

08.09.1960

[न्यायाधिपतिगण – एस.के. दास, एम. हिदायतुल्ला, के.सी. दास गुप्ता, जे.सी. शाह व एन. राजगोपाला अयंगर]

वाद की पोषणीयता - इस्तिमरारी जागीर - विधवा के द्वारा दत्तक गृहण के तथ्य एवं वैधता को चुनौती देने का वाद - केन्द्र सरकार द्वारा दत्तक की पुष्टि का कानून बनाना और वाद करने का सशर्त अधिकार – वाद का वर्जन – अजमेर भू-राजस्व विनियमन 1877 (1877 का विनियमन 11) धारा 23, 24, 119.

B की मृत्यु के बाद 28.09.1947 को इस्तिमरारी जागीर के धारक के कोई पुरूष संतान नहीं थी। कार्ट ऑफ़ वाड्र्स ने जागीर कब्जे में लेकर अजमेर भू एवं राजस्व विनियमन 1877 के तहत नोटिस जारी किया तथा जागीर के सम्बन्ध में दावे आमंत्रित किये। जब जांच विचाराधीन थी एक प्रार्थना पत्र अपीलांट ने पेश किया कि दिनांक 24.02.1948 को अपीलांट को B की विधवा ने दत्तक गृहण किया है। तथा उक्त कृत्य उक्त विनियम की धारा 23 के

तृतीय परन्तुक के तहत पुष्टि किये जाने योग्य है। 10.09.1951 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दत्तक की पुष्टि की गई। तत्पश्चात प्रत्यर्थी सं. 1 ने घोषणा का

वाद प्रस्तुत किया कि अन्य बातें के बीच कि अपीलांट दत्तक नहीं थे तथा विकल्प में दत्तक गृहण गैरकानूनी एवं अवैध है। अपीलांट ने अपनी प्रतिरक्षा में अभिवचन किया कि केन्द्र सरकार के द्वारा दत्तक की पुष्टि किये जाने के पश्चात यह माना जावेगा कि दत्तक के तथ्यों की वैधता जांच ली गई है। इस प्रकार का प्रश्न विनियमन की धारा 23 एवं धारा 119 के तहत सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी इसलिए वाद पोषणीय नहीं था।

अभिनिर्धारित (न्यायाधिपति एस.के. दास, असहमति) (1) यद्यपि धारा 23 अजमेर भू राजस्व विनियमन 1877 की धारा 23 के तहत एक विधवा द्वारा दत्तक गृहण किया जाना तब तक वैध नहीं माना जावेगा जब तक कि वह केन्द्र सरकार द्वारा पुष्ट न कर दिया जावे। दत्तक की ऐसी पुष्टि अपने आप वैध नहीं हो जाती यदि यह सामान्य विधि के तहत अन्यथा अवैध है। और (2) कि विनियम की धारा 119(1) जो एक बात केन्द्र सरकार के द्वारा पुष्टि को आदेशित या विनिश्चित की गई हो पर महाभियोग नहीं हो सकता परन्तु पुष्टि किये जाने से यह विविक्षित रूप से नहीं निकलता या प्रत्यक्ष नहीं है कि सिविल न्यायालय को पक्षकारों के कृत्यों या तथ्यों की परीक्षा की क्षेत्राधिकारिता न हो जो पुष्टिकरण की कार्यवाही से पहले था।

इसके अनुसार सिविल न्यायालय के समक्ष वर्तमान में लाया गया वाद दत्तक की पुष्टि के बारे में अनुतोष का नहीं है बल्कि दत्तक को अवैध घोषित करवाने का है जो विनियम की धारा 23 एवं 119 के तहत वर्जित नहीं है।

न्यायाधिति एस.के दास के अनुसार – विनियम की धारा 23 के तृतीय परन्तुक में जो पुष्टि बताई गई है उसमें दो तथ्यों का निर्धारण जो आवश्यक है समाहित है जैसे (a) क्या विधवा के पास दत्तक गृहण की शक्ति है (b) क्या उसने वास्तव में इस्तेमारदार के लिए एक पुत्र को दत्तक लिया, अन्यथा उक्त तथ्यों के अलावा पुष्टिकरण का कोई अर्थ नहीं है। और समझने योग्य कोई सामग्री नहीं है क्योंकि धारा 119 के तहत पुष्टिकरण के निर्णय के विरूद्ध कोई वाद नहीं लाया जा सकता। विनियमन की धारा 23 एवं धारा 119 के उचित निर्माण पर वर्तमान वाद विधि द्वारा वर्जित है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील नं. 8/1955

पूर्व न्यायिक आयुक्त न्यायलय, अजमेर के सिविल प्रथम अपील नं. 28/1953 के निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध अपील की विशेष अनुमति -

ए.वी. विश्वेन्द्र शास्त्री, जे.बी. दादाचन जी, रामेश्वर नाथ व पी.एल. वोरा - अपीलांट की और से।

बी.सेन व आई एन. श्राॅफ – प्रत्यर्थी की और से।

08.09.1960 – न्यायाधिपतिगण एम. हिदायतुल्लाह, के.सी. दास गुप्ता, जे.पी. शाह व एन. राजगोपाला अयंगर द्वारा निर्णय, न्यायाधिपति हिदायतुल्ला द्वारा पारित किया गया। न्यायाधिपति एस. के. दास ने पृथक से निर्णय पारित किया।

न्यायाधिपति हिदायतुल्लाह – 7 जनवरी 1954 को न्यायिक आयुक्त अजमेर द्वारा पारित निर्णय जिसमें प्रथम प्रत्यर्थी के वाद खारिज किया गया प्रथम अपील सं. 28/1953 में वरिष्ठ अधिनस्थ न्यायाधीश अजमेर द्वारा निर्णय को उलट दिया गया।

मामले के तथ्य इस प्रकार हैं - ठाकुर बंसप्रदीप सिंह सांवर के इस्तिमारदार थे, उनकी मृत्यु 28.09.31947 को हुई जिनके कोई पुरूष संतान न तो जन्मी थी और न दत्तक ली गई थी। उनकी मृत्यु के बाद कार्ेट ऑफ़ वाड्र्स ने जागीर कब्जे में लेकर धारा 24 अजमेर भू एवं राजस्व विनियम 1877 (1877 का विनियम 11) के तहत जागीर पर दावों को आमंत्रित करने के लिए नोटिस जारी किया। ठाकुर लक्ष्मणसिंह (प्रत्यर्थी सं. 1) के पिता ठाकुर खुमानसिंह, ठाकुर बृजराजसिंह (अपीलांट नं. 1) तथा रूध ठाकुर इंदरसिंह (प्रत्यर्थी सं. 2) ने दावा किया। जब यह जांच लम्बित थी ठाकुर खुमानसिंह की मृत्यु हाे गई। तब ठाकुर लक्ष्मणसिंह का नाम उनके स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। जांच के दौरान उपआयुक्त ने कुछ अन्तर्वर्ती मामले मुख्य आयुक्त को रेफर किये और मुख्य आयुक्त ने

मामलों को सुनवाई हेतु 25.02.1948 को नियत किया। उस दिन इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि रानी बाघेली जी के द्वारा ठाकुर बृजराजिसंह को दिनांक 24.02.1948 को दत्तक लिया गया है। तथा मुख्य आयुक्त द्वारा मामला गवर्नर जनरल को विनियम की धारा 23 के तृतीय परन्तुक के तहत पुष्टि के लिए भेजा जावे। वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से ऐसा प्रकट होता है कि उक्त प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया क्योंकि 10.09.1951 को भारत सरकार के सचिव, खाद्य एवं कृषि विभाग मंत्रालय ने अवगत करवाया कि भारत के राष्ट्रपति ने दत्तक गृहण की पुष्टि की है। मामला गवर्नर जनरल को आवश्यक रूप से रेफर किया जाना चाहिए था।

ठाकुर लक्ष्मणसिंह ने इसके पश्चात वर्तमान वाद ठाकुर बृजराजिसंह, सावर की रानी बाघेली जी तथा रूध के इन्दरसिंह को प्रतिवादी बनाते हुए प्रस्तुत किया। अन्य अनुतोषों के साथ निम्न दो अनुतोष चाहे गए -

"कि यह घोषित किया जा सकता हैः-

(a) प्रत्यर्थी सं. 1, प्रत्यर्थी सं. 2 के द्वारा दत्तक नहीं लिया गया है और वह उसका दत्तक पुत्र नहीं है। तथा विकल्प में प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा प्रत्यर्थी सं. 1 का किया गया दत्तक ग्रहण अवैध एवं गैरकानूनी है। और -

(b) कि वादी स्वर्गीय ठाकुर बंसप्रदीपसिंह का निकटतम परिजन और उत्तराधिकारी है।''

योग्य अधीनस्थ न्यायाधीश ने उक्त अनुतोषों पर कोई विवाद्यक विरचित नहीं किया बल्कि एक प्रारम्भिक विवाद्यक विरचित किया -

''आया धारा 24 व 119 अजमेर भू एवं राजस्व विनियम 1877 के तहत वाद विधि द्वारा वर्जित है?''

उसने अभिनिर्धारित किया कि ये दोनों धाराएं वाद को वर्जित करती है और दावा मय खर्चा खारिज किया। न्यायिक आयुक्त अजमेर को अपील किये जाने पर वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश का निर्णय पलट दिया गया। इसके पश्चात ठाकुर बृजराजसिंह व रानी बाघेली जी ने संविधान के अनुच्छेद 133(1)(a) और (c) के तहत विद्वान न्यायिक आयुक्त के समक्ष प्रमाण पत्र चाहा जो उनके द्वारा मना कर दिया गया क्योंकि उनकी राय में उनका निर्णय अन्तिम नहीं था। तब इस न्यायालय के सामने विशेष अनुमति याचिका पेश की गई जाे स्वीकार कर वर्तमान अपील प्रस्तुत हुईः-

हम इस अपील में दलीलों और दावे की प्रकृति के प्रकाश में विनियमन की धारा 23, 24 एवं 119 की व्याख्या से चिंतित है। इससे पहले कि हम इन धाराआेंं का निर्धारण करें हमारी इच्छा है कि हम विनियम के सामान्य अन्य प्रावधानों का इस मामले पर असर का परीक्षण

करें। प्रश्नगत विनियमन 6 भागों में विभाजित है तथा द्वितीय भाग भूमि

के कुछ हितों के बारे में है जो अन्य बातों के साथ ही ऐसी भूमि के धारकों के उत्तराधिकार को दिलाता है। भाग द्वितीय अपने आपमें 9 धाराओं में विभाजित है तथा धारा c इस्तिमरारी जागीर से सम्बन्धित है। धारा 20 ''इस्तिमरारी जागीर'' को परिभाषित करती है जिसके सम्बन्ध में विनियमन पारित होने से पहले गवर्नर जनरल इन काउंसिल की पूर्व मंजूरी के साथ मुख्य आयुक्त द्वारा इस्तिमरारी सनद प्रदान की गई है। धारा को बाद में पारित अनुकूलन आदेशों द्वारा संशोधित किया गया है जो अब बहुत परिचित तरीके से है। ''इस्तमरारदार'' को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे ऐसी सनद दी गई है या ''कोई अन्य व्यक्ति जो उत्तराधिकार से इस्तिमरारी सम्पत्ति का हकदार बन जाता है जैसा कि इसके बाद प्रदान किया गया है।'' उत्तराधिकार के नियम की धारा 23 और 24 के पाए जाते हैं, धारा 23 जहां जागीर में पुरूष संतान विद्यमान है वहां तथा धारा 24 जहां कोई पुरूष संतान नहीं है वहां उत्तराधिकार प्रदान करती है। धारा C का शेष खण्ड किरायेदारों, सम्पत्ति के अन्य संक्रामण, रखरखाव, जप्ती इत्यादि से सम्बन्धित है जिनसे हमारा कोई लेना देना हैं। इस तरह धारा 23 और 24 से इस्तिमरारी जागीर का उत्तराधिकार प्रशासित होता है और उसमें उत्तराधिकार का कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उक्त धाराओं में दिये अनुसार हल किया जाना चाहिए।

धारा 23 इस प्रकार हैः-

''जागीर का उत्तराधिकार जहां पुरूष संतान हैः-

जब एक इस्तिमरादार पुत्रों या पुरूष संतान को छोड़कर जाता है तब उत्तराधिकार केवल पुरूषों के माध्यम से होगा चाहे जन्म या दत्तक द्वारा या जब इस्तिमरारदार की मृत्यु के बाद उसकी विधवा को गोद लेने की शक्ति होती है और उसके लिए पुत्र को गोद लेती है। इस्तिमरारी सम्पत्ति मृतक के परिवार की रीति अनुसार यथा सम्भव हस्तांतरित की जावेगी। बशर्तेः-

प्रथम - ज्येष्ठाधिकार का नियम – कि सभी मामलों में वंश का ज्येष्ठाधिकारी उत्तराधिकारी होगा।

द्वितीय - कौनसा दत्तक वैध है - कोई भी दत्तक तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक कि वह कलेक्टर या जिले के रजिस्ट्रार के पास लिखित दस्तावेज के द्वारा न बनाया गया हो।

तृतीय - विधवा द्वारा दत्तक - विधवा द्वारा लिया गया दत्तक वैध नहीं माना जावेगा जब तक कि केन्द्र सरकार द्वारा पुष्टि न की गई हो।

परस्पर विरोधी पक्षकारों के तर्क तीसरे परन्तुक की व्याख्या के बारे में है जिसे धारा में शुरूआती शब्दों के साथ लिया गया है। एक पक्ष का तर्क है कि गोद लेने की पुष्टि के बाद कोई विवाद नहीं बचता है जो धारा 119 में निहित रोक के मद्देनजर सिविल कोर्ट में जा सकता है। जिसका हम वर्तमान में उल्लेख करेंगे। दूसरे पक्ष का तर्क है कि धारा 24 के

शुरूआती शब्दों को देखते हुए धारा 23 के अन्तर्गत प्रश्न सिविल

न्यायालय से निपटारे के लिए ले जाया जा सकता है। तथा धारा 119 इस पर कोई वाद वर्जित नहीं करती है।

धारा 24 तथा 119 को अब उद्धृत किया जा सकता हैः-

धारा 24 – जहां पुरूष संतान नहीं है वहां उत्तराधिकार - धारा 23 द्वारा प्रदान नहीं किये गए मामलों में उत्पन्न होने वाली एक जागीर के उत्तराधिकार के अधिकार के बारे में कोई प्रश्न केन्द्र सरकार या ऐसे अधिकारी के द्वारा तय किया जाएगा जिसे वह इस सम्बन्ध में नियुक्त कर सकती है बशर्ते कि केन्द्र सरकार यदि वह उचित समझती है तो ऐसे प्रश्न पर स्वयं निर्णय लेने या उसे तय करने के लिए किसी अधिकारी को नियुक्त करने के बजाए उपरोक्त सफल होने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति काे यह घोषणा करते हुए एक प्रमाण पत्र दे सकती है कि मामला सिविल न्यायालय द्वारा विनिश्चित करने के लिए उचित है।

जिस व्यक्ति को ऐसा प्रमाण पत्र दिया गया है वह अपने ऐसे अधिकार को स्थापित करने के लिए किसी सक्षम न्यायालय में वाद संस्थित कर सकता है जो तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन ऐसे मामलों का विचारण कर सकता है और ऐसा न्यायालय जिसके समक्ष प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है ऐसे दावों की सुनवाई कर सकता है।

धारा 119 सिवाय इसके कि इससे पहले स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है -

(a) विनियमन के तहत कार्यवाही जहां नियोजित नहीं होगी-

इस विनियमन के तहत वे सभी कृत्य, आदेश विनिश्चय जो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या राजस्व अधिकारी द्वारा किए गए हैं यह माना जावेगा कि वे विधिक रूप से सही से आदेशित या विनिश्चित किये गए हैं।

(b) सिविल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार की सीमाः-

इस विनियमन के तहत सशक्त केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या राजस्व अधिकारी द्वारा पारित किये गए किसी भी आदेश या निर्णय के विरूद्ध सिविल न्यायालय किसी भी संस्थित वाद या प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की सुनवाई नहीं करेगा।''

इससे पहले कि हम इन धाराआेंं पर विचार करें मामले की प्रकृति पर संक्षेप में जांच करना आवश्यक है क्याेंकि धारा 23 और धारा 24 विभिन्न प्रकार के मामलों पर विचार करती है। जिन मुख्य अनुतोषों का दावा किया गया है वे हमारे द्वारा पहले ही निर्धारित किये जा चुके हैं। यह देखा जाएगा कि दो घोषणात्मक अनुतोषों का दावा किया गया है। पहला जो दो भागों में है, यह कि ठाकुर बृजराजसिंह की रानी बाघेली जी ने दत्तक नहीं लिया था और यह दत्तक अमान्य और अवैध था। यह धारा 23 के अन्तर्गत आने वाला मामला है न कि धारा 24 में। दूसरा अनुतोष इस घोषणा के लिए है कि वादी स्वर्गीय ठाकुर बंसप्रदीप सिंह का निकटतम परिजन है और उत्तराधिकारी है। यदि ठाकुर बंसप्रदीप सिंह ने जन्म या

दत्तक से कोई पुरूष संतान नहीं छोड़ी है तो मामला प्रथम दृष्टया धारा 24 से प्रशासित होगा। यह धारा वांछा करती है कि ऐसा विवाद केन्द्र सरकार या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जावे। हालांकि एक परन्तुक यह है कि केन्द्र सरकार ऐसे प्रश्न पर स्वयं निर्णय लेने या निर्णय लेने के लिए किसी अधिकारी को नियुक्त करने के बजाय ऐसे व्यक्ति को जो सफल होने का दावा करता है यह घोषणा करते हुए प्रमाण पत्र जारी कर सकती है कि मामला सिविल न्यायालय द्वारा निस्तारित किये जाने के लिए उचित मामला है। प्रथम दृष्टया इसलिए यदि मामला केवल धारा 24 के अन्तर्गत आता है तो वादी बिना ऐसे प्रमाण पत्र के वाद संस्थित नहीं कर सकता है। हमें उन तथ्यों पर गुणावगुण पर अपनी राय व्यक्त करना आवश्यक नहीं है जो तथ्य न्यायालय के निर्णय के लिए प्रस्तुत किये जाने हैं क्योंकि मामला ऐसे पूर्ववर्ती स्तर पर है जहां ऐसे तर्क उचित रूप से उठाए जा सकते हैं। तृतीय अनुतोष मूल रूप से ठाकुर बृजराजसिंह के खिलाफ एक स्थाई निषेधाज्ञा का दावा किया गया था जिसमें उनके खिलाफ दत्तक गृहण का प्रश्न तय किया जाना चाहिए, उन्हें मूल वाद लड़ना होगा जिसके लिए विनियम की धारा 24 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया है। तृतीय अनुतोष निषेधाज्ञा का था जो संशोधित वाद पेश किया गया तब डिलीट कर दिया गया।

धारा 23 के अन्तर्गत आने वाले मामलों में विनियम की धारा 24 स्वयं को बाहर रखती है। धारा 23 उत्तराधिकार से सम्बन्धित है जब

कोई पुरूष संतान जन्म से या दत्तक से उत्तराधिकार प्राप्त करती है और आगे कहा गया है कि इस्तिमरारी जागीर जितना संभव हो सके मृतक के परिवार में रीति के अनुसार हस्तांतरित होगी। सही उत्तराधिकारी का पता लगाने के लिए यह जांचना आवश्यक हो सकता है कि पारिवारिक रीति रिवाज क्या है। यह जांच धारा 24 के शुरूआती शब्दों से की जा सकती है। किसी भी विवाद के समाधान के लिए कोई अन्य मंच सूचित नहीं किया गया है जो प्रतिद्वंदी दावेदारों के बीच उत्पन्न हो सकता है। जहां एक दावेदार एक पुरूष संतान के रूप में मृतक इस्तिमारदार के उत्तराधिकारी बनना चाहता है ऐसे विवाद जो एक बार उत्पन्न हो सिविल न्यायालय के समक्ष जा सकते हैं जिसका अधिकार क्षेत्र जैसा एक से अधिक अवसरों पर कहा गया है तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि कानून द्वारा ऐसा व्यक्त न किया गया हो या स्पष्ट रूप से इसमें निहित न किया गया हो। धारा 23 में ऐसे में कोई प्रत्यक्ष शब्द नहीं है कि सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार विवर्जित हो तथा प्रश्न जो विचारणीय है वह यह है कि क्या ऐसी कोई चीज है जो अपने स्पष्ट इरादे से एक ही परिणाम तक पहुंचती है।

अपीलांट्स के अनुसार, धारा 23 के तृतीय परन्तुक में कहा गया है कि दत्तक गृहीता विधवा को केंद्र सरकार से पुष्टि प्राप्त करनी चाहिए और

चूंकि केंद्र सरकार को मामले पर विचार करते समय दो बिंदुओं पर निर्णय लेना होता है, अर्थात् विधवा को दत्तक गृहण की शक्ति थी और

वास्तव में, उसने मृतक के लिए दत्तक लिया था, दत्तक की पुष्टि होने पर उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तय किया गया माना जाना चाहिए, और धारा 119 के पहले खंड को ध्यान में रखते हुए, यह कुछ ऐसा है जो "केंद्र सरकार द्वारा किया गया, आदेश दिया गया या निर्णय लिया गया है।" जिसे "कानूनी रूप से और सही ढंग से किया गया, आदेश दिया गया या निर्णय लिया गया माना जाना चाहिए"। इस तथ्य का भी संदर्भ दिया गया है कि जब दत्तक का विलेख पहली बार मुख्य आयुक्त के ध्यान में लाया गया था और इसकी पुष्टि की मांग की गई थी, तो विपक्षी पक्षकार ने अनुरोध का विरोध किया था। इसलिए, अपीलांट्स द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पुष्टि कर दी गई है, मामले में कोई विवाद नहीं बचा है और सिविल कोर्ट को निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है।

इस संबंध में धारा 33 और 34 को देखना दिलचस्प है, जो 'भूम' के उत्तराधिकार से संबंधित है, जिसका अर्थ है वह भूमि जिसके संबंध में भूम सनद दी गई हो। धारा 33 इस प्रकार है:

> "भौम को उत्तराधिकार जहां पुरुष संतान है - जब कोई भूमिया पुत्रों को छोड़कर मर जाता है या पुरूष संतान केवल पुरूषों के माध्यम से उत्पन्न होती है चाहे वह जन्म से हो या दत्तक से या जब भूमिया की मृत्यु के बाद उसकी विधवा

दत्तक लेती है तब भूम परिवार की रीति के अनुसार हस्तांतरित की जाएगी।"

धारा 34, जो धारा 24 से मेल खाती है, इप्सिस्सिमा वर्बा है, सिवाय इसके कि "भूम" एक "इस्तिमरारी एस्टेट" की जगह लेता है। यदि धारा 33 और 34 को एक साथ पढ़ा जाता है, तो इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है कि जो मामला धारा 33 के अंतर्गत आता है, वह धारा 34 के संचालन से अलग है, और कोई दावा बाद की धारा के शुरुआती शब्दों के कारण प्रभावित नहीं होता है। अब, धारा 23 की तुलना धारा 33 से की जा सकती है।

धारा 23 और धारा 33 में अंतर केवल इतना है कि पहले वाले खंड में तीन शर्तों का उल्लेख है. पहली शर्त के द्वारा, ज्येष्ठाधिकार का कानून लागू किया जाता है, दूसरी शर्त के द्वारा कलेक्टर या जिले के रजिस्ट्रार के पास जमा लिखित रूप में एक विलेख की आवश्यकता होती है, और तीसरी शर्त के द्वारा दत्तक के मामले में दत्तक गृहण की पुष्टि की जाती है किसी विधवा को, केंद्र सरकार से दत्तक का अनुमोदन लेना होगा। हमारी राय में, धारा 23 के अंतर्गत मामले भी धारा 33 के समान ही सिविल न्यायालय के समक्ष जा सकते हैं। धारा 23 के अंतिम दो परन्तुक दो स्थितियाँ बनाती हैं जिन्हें एक विधवा को दत्तक को वैध मानने से पहले उसे पूरा करना होगा। दत्तक को वैध होने के लिए हिंदू कानून की

आवश्यकताओं का पालन करना होगा और विधायिका ने दो अन्य शर्तें जोड़ी हैं। ये शर्तें केवल यह कहती हैं कि कोई भी दत्तक "वैध नहीं माना जाएगा" जब तक कि उनका अनुपालन भी किया जाता है। पहली शर्त यह है कि दत्तक गृहण एक लिखित दस्तावेज द्वारा होना चाहिए, जिसे कलेक्टर, जिले के रजिस्ट्रार के पास जमा किया जाना चाहिए, और दूसरी यह है कि इसकी पुष्टि केंद्र सरकार द्वारा की जानी चाहिए। जैसा कि विलेख का जमा किया जाना आवश्यक है अन्यथा अमान्य दत्तक को मान्य नहीं किया जा सकता है। यदि यह सामान्य कानून के तहत अन्यथा अमान्य है, तो पुष्टिकरण, अपने आप में दत्तक गृहण को वैधता प्रदान नहीं करता है, बल्कि केवल विधायिका द्वारा बनाई गई शर्त को पूरा करता है। यदि वह कमी बनी रहती है, तो दत्तक गृहण वैध नहीं माना जा सकता, भले ही वह हर दूसरे दृष्टिकोण से वैध हो। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि परंतुक नकारात्मक में व्यक्त किया गया है। इसमें यह नहीं कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा पुष्टि किए जाने पर दत्तक गृहण वैध माना जाएगा। जबकि पुष्टि के दत्तक गृहण को वैध नहीं माना जा सकता है, केंद्र सरकार द्वारा पुष्टि की गई दत्तक की पुष्टि से जुड़े आधारों के अलावा अन्य आधारों पर भी प्रहार किया जा सकता है।

अपीलांट का तर्क है कि विनियमन की धारा 119 के कारण इसकी पुष्टि के बाद दत्तक की वैधता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। धारा 119 केवल केंद्र सरकार द्वारा किए गए, आदेशित या निर्णय किए गए

किसी भी कार्य को न्यायिक जांच से बाहर कर देती है। धारा का शीर्षक पहले खंड के आयात को बहुत स्पष्ट रूप से सामने लाता है, और वह यह है कि विनियमन के तहत कार्यवाही पर महाभियोग नहीं लगाया जाना चाहिए। एकमात्र चीज जो की जाती है, आदेश दिया जाता है या निर्णय लिया जाता है वह है पुष्टिकरण, और यद्यपि पुष्टिकरण पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है, पुष्टिकरण के लिए कार्यवाही शुरू होने से पहले जो कुछ भी होता है वह संरक्षित नहीं है। जब पुष्टि की कार्यवाही शुरू होती है, तो पुष्टि की मांग करने वाला पक्ष तथ्यों के साथ केंद्र सरकार के पास जाता है, और हालांकि केंद्र सरकार खुद को संतुष्ट कर सकती है, पुष्टि देने का निर्णय तथ्यों की जांच करने के लिए सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को खत्म नहीं करता है और पक्षकारों के कार्य, जो पुष्टिकरण की कार्यवाही से पहले हुए। धारा 23 में विधायिका ने यह बात स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से नहीं कही है। विधवा को दत्तक गृहण की शक्ति होनी चाहिए और वास्तव में, उसे एक पुत्र को दत्तक लेना चाहिए, ये ऐसे मामले हैं जिन पर पुष्टिकरण के प्रयोजनों के लिए विचार किया जा सकता है; लेकिन दत्तक गृहण की वैधता अभी भी एक मामला है, जिस पर सिविल कोर्ट विचार कर सकता है, इसमें कोई स्पष्ट या निहित शब्द नहीं है जिससे दत्तक गृहण की वैधता निर्णायक रूप से स्थापित हो। धारा 119 के पहले खंड की शक्ति केवल केंद्र सरकार द्वारा किए गए, आदेशित या निर्णय किए गए किसी कार्य के रूप में पुष्टि को बनाए रखने के लिए है, जिसे

कानूनी रूप से और सही ढंग से किया गया, आदेश दिया गया या निर्णय लिया गया माना जाना चाहिए। इसका दत्तक गृहण पर कोई असर नहीं है क्योंकि यह विनियमन के तहत केंद्र सरकार द्वारा किया गया, आदेशित या निर्णय नहीं किया गया था।

धारा 119 का द्वितीय खंड जो कुछ मामलों में सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार को सीमित करता है, वह भी लागू नहीं होता है। वह खंड पहले ही उद्धृत किया जा चुका है। वाद में पहला विवाद्यक किसी भी आदेश या निर्णय को प्राप्त करना शामिल नहीं करता है, जिसे केंद्र सरकार, विनियमन के तहत, बनाने या सुनाने के लिए सशक्त है। केंद्र सरकार ने दत्तक गृहण की पुष्टि कर दी है. यह वाद सिविल कोर्ट से पुष्टि प्राप्त करने के लिए नहीं है बल्कि दत्तक गृहण को अवैध घोषित कराने के लिए है। मामले में वादी सिविल कोर्ट से आदेश प्राप्त करने की मांग नहीं कर रहा है, जिसे लागू करने का अधिकार विनियमन केंद्र सरकार को देता है। केंद्र सरकार को पुष्टिकरण आदेश देने का अधिकार है, लेकिन वाद में ऐसे आदेश की मांग नहीं की जा रही है जो मांगा जा रहा है वह दत्तक गृहण की वैधता की जांच है, और जैसा कि हम पहले ही ऊपर दिखा चुके हैं, यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिस पर केंद्र सरकार का निर्णय निश्चायक बना दिया गया है।

हमारी राय में, इसलिए पहले अनुतोष के संबंध में वाद सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। दूसरा अनुतोष प्रथम दृष्टया धारा 24 को आकर्षित करता है, और इसकी शर्तों का पालन करना होगा। इस प्रकार वाद तो चलना ही होगा। मामले की परिस्थितियों में न्यायिक आयुक्त का आदेश सही था और हमें इससे अलग होने का कोई कारण नहीं दिखता। परिणामस्वरूप, अपील विफल हो जाएगी और जुर्माने सहित खारिज कर दी जाएगी।

न्यायाधिपति एस.के. दास, जे.

बहुत अफसोस के साथ मैं इस विवाद्यक पर अपने विद्वान भाइयों से अलग निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि क्या वाद अजमेर भूमि और राजस्व विनियमन, 1877 (1877 के विनियमन संख्या II) की धारा 119 के प्रावधानों के तहत वर्जित है। , जिसे इसके बाद विनियम के रूप में जाना जाएगा। मेरा निष्कर्ष यह है कि मुकदमा वर्जित है और मैं शीघ्र ही उन कारणों को बताने जा रहा हूं जिनके कारण मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं।

प्रासंगिक तथ्य मेरे विद्वान भाइयों की ओर से सुनाए गए फैसले में बताए गए हैं, और उन्हें दोबारा बताना आवश्यक नहीं है। मुझे

केवल यह जोड़ना है कि वादी जो अब हमारे सामने प्रतिवादी नंबर 1 है, एक घोषणा के लिए मुकदमा लेकर आया था कि प्रतिवादी नंबर 1 (अब अपीलांट नंबर 1) को प्रतिवादी नंबर 2 (अब अपीलांट नंबर 2) द्वारा एक

तथ्य के रूप में नहीं अपनाया गया था। तथ्य के रूप में स्थापित होने पर भी दत्तक गृहण अमान्य और अवैध था; प्रत्यर्थी नंबर 1, ठाकुर बंसप्रदीप सिंह का निकटतम रिश्तेदार और उत्तराधिकारी था और इस तरह सावर की जागीर और उनके द्वारा छोड़ी गई सभी संपत्तियों और परिसंपत्तियों का उत्तराधिकारी होने का हकदार था; अपीलांट नंबर 1 को सावर की संपत्ति में दखल देने और हस्तक्षेप करने से हमेशा के लिए रोका जाए; और सावर की संपत्ति और उसकी सभी चल और अचल संपत्ति का एक रिसीवर नियुक्त किया जाएगा। वादपत्र में बाद में संशोधन किया गया और स्थायी निषेधाज्ञा और घोषणा के लिए अनुतोष दिया गया कि प्रत्यर्थी नंबर 1 सावर की संपत्ति में सफल होने का हकदार था, संभवतः इसलिए क्योंकि इस तरह के अनुतोष के लिए वाद विनियमन की धारा 24 के तहत स्पष्ट रूप से वर्जित होगा। अब विचार करने वाली बात यह है कि क्या वाद, संशोधित वादपत्र पर भी, विनियमन की धारा 23 के साथ पढ़ी गई धारा 119 के प्रावधानों के तहत वर्जित है।

अब विनियम के कुछ प्रासंगिक प्रावधानों को पढ़ना आवश्यक है। धारा 20 एक "इंस्टिमररी एस्टेट" को परिभाषित करती है और यह विवादित नहीं है कि सावर की जागीर एक ऐसी जागीर है जो धारा 21 "

इस्तिमारारी संपत्ति" में किरायेदारों की स्थिति को परिभाषित करती है। धारा 22 ऐसी संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित है और फिर धारा 23 आती है जिसे पूरा पढ़ा जाना चाहिए:

"धारा 23. संपत्ति का उत्तराधिकार जहां पुरुष संतान है: जब एक इस्तिमरदार अपने पुत्रों को छोड़कर मर जाता है या पुरुष पुत्र पैदा होता है जो केवल पुरुषों के माध्यम से होता है, चाहे जन्म या दत्तक के द्वारा या जब इस्तिमरदार की मृत्यु के बाद उसकी विधवा को दत्तक गृहण की शक्ति होती है उसके पुत्र को, इस्तिमारारी संपत्ति मृतक के परिवार की रीति के अनुसार यथासंभव हस्तांतरित की जाएगी; बशर्ते -

पहला, ज्येष्ठाधिकार का नियम - कि वंश ज्येष्ठाधिकार के नियम के अनुसार सभी मामलों में एक ही उत्तराधिकारी का होगा;

दूसरा, कौन सा दत्तक गृहण वैध है - कोई भी दत्तक तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक कि वह कलेक्टर या जिले के रजिस्ट्रार के पास जमा किए गए लिखित दस्तावेज द्वारा न बनाया गया हो;

तीसरा, विधवा द्वारा दत्तक गृहण - कि किसी विधवा द्वारा लिया गया कोई भी दत्तक तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक कि केंद्र सरकार इसकी पुष्टि न कर दे।"

धारा 24 कहती है:

"धारा 24. संपत्ति का उत्तराधिकार जब कोई पुरुष संतान न हो: - धारा 23 द्वारा प्रदान नहीं किए गए मामले में उत्पन्न होने वाली संपत्ति के उत्तराधिकार के अधिकार के बारे में कोई भी प्रश्न केंद्र सरकार, या ऐसे अधिकारी द्वारा तय किया जाएगा वह इस संबंध में नियुक्ति कर सकता है।

बशर्ते कि केंद्र सरकार, यदि वह उचित समझती है, तो ऐसे प्रश्न पर स्वयं निर्णय लेने या उसे तय करने के लिए किसी अधिकारी को नियुक्त करने के बजाय, उपरोक्त सफल होने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को यह घोषणा करते हुए एक प्रमाण पत्र दे सकती है कि मामला सिविल न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाना उचित है।

जिस व्यक्ति को ऐसा प्रमाण पत्र दिया गया है, वह किसी भी न्यायालय में अपना अधिकार स्थापित करने के लिए वाद दायर कर सकता है अन्यथा उस पर वाद चलाने के लिए उस समय लागू कानून के तहत सक्षम है, और ऐसा न्यायालय, इससे पहले कि वह ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे, उस पर विचार कर सकता है।

उन प्रावधानों को छोड़ देना जो हमारे सामने मौजूद मुद्दे पर विचार करने के लिए सीधे तौर पर प्रासंगिक नहीं हैं। मैं धारा 119 पर आता हूं जो इन शर्तों में है:

"धारा 119. सिवाय इसके कि इससे पहले स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है -

(ए) विनियमन के तहत कार्यवाही पर महाभियोग नहीं लगाया जाएगा: - इस विनियमन के तहत केंद्र सरकार, राज्य सरकार या राजस्व अधिकारी द्वारा किया गया, आदेश दिया गया या निर्णय लिया गया सब कुछ कानूनी रूप से और सही ढंग से किया गया या आदेश दिया गया या निर्णय लिया गया माना जाएगा;

(बी) सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र की सीमा - कोई भी सिविल न्यायालय किसी भी आदेश या निर्णय को प्राप्त करने की दृष्टि से दायर या प्रस्तुत किए गए किसी भी वाद या आवेदन पर विचार नहीं करेगा, जिसे बनाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार या एक राजस्व अधिकारी इस विनियमन के तहत सशक्त है या उच्चारण करें।"

निर्णय के लिए प्रश्न यह है कि क्या वाद विनियम की धारा 23 के साथ पठित धारा 119 के प्रावधानों के तहत वर्जित है। इस प्रारंभिक

वाद की सुनवाई करने वाले वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश ने माना कि वाद वर्जित था; अपील पर विद्वान न्यायिक आयुक्त विपरीत निष्कर्ष पर पहुंचे। प्रश्न का उत्तर उपरोक्त दोनों धाराओं के प्रावधानों के वास्तविक दायरे और प्रभाव पर निर्भर करता है। मैं इस आधार पर आगे बढ़ता हूं कि कानून का सामान्य नियम यह है कि जब किसी कानूनी अधिकार और उसके उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है, तो कार्रवाई के कारण का खुलासा किया जाता है और जब तक वाद के विचारण पर कोई वर्जन नहीं होता है, तब तक सामान्य सिविल न्यायालय विचार करने के लिए बाध्य होते हैं। वाद का वर्जन स्पष्ट या आवश्यक निहितार्थ द्वारा हो सकता है। एक उचित निर्माण पर, क्या विनियम की धारा 23 और 119 इस तरह का वर्जन करती है?

मेरे विचार में, वे ऐसा करते हैं। धारा 23 का मूल भाग, जहां तक यह विचाराधीन बिंदु के लिए प्रासंगिक है, दो तथ्यों को संदर्भित करता है: (1) विधवा को दत्तक गृहण की शक्ति है, और (2) उसने वास्तव में दिवंगत इस्तिमारदार को एक पुत्र दत्तक लिया है। इन दो तथ्यों के मौजूद

होने पर, धारा 23 अपने मूल भाग में कहती है कि संपत्ति मृतक के परिवार के रीति-रिवाजों के अनुसार यथासंभव हस्तांतरित की जाएगी। मूल भाग के बाद तीन परंतुक आते हैं; हम केवल तीसरे प्रावधान से चिंतित हैं, जो कहता है कि किसी विधवा द्वारा किया गया कोई भी दत्तक तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक कि केंद्र सरकार इसकी पुष्टि न कर दे। वर्तमान मामले में पुष्टि का ऐसा आदेश दिया गया था। प्रावधान को दोहरे

नकारात्मक के रूप में व्यक्त किया गया है, और सकारात्मक रूप में रखा गया है, इसका मतलब है कि एक विधवा द्वारा किया गया दत्तक गृहण धारा 23 के प्रयोजन के लिए वैध होगा, जब इसकी पुष्टि केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। एक दृष्टिकोण से, यह एक अतिरिक्त शर्त है और दूसरे दृष्टिकोण से, यह दत्तक गुहण की शक्ति और दत्तक गृहण के तथ्य के निर्धारण को अपने भीतर समाहित करता है; स्पष्ट कारणों से, रिक्त स्थान में पुष्टि का आदेश नहीं दिया जा सकता है। इसकी पुष्टि होने से पहले दत्तक गृहण आवश्यक है। मेरी राय में, पुष्टिकरण आदेश के सही अर्थ और सामग्री की सराहना करने के लिए तीसरे परन्तुक को धारा 23 के मूल प्रावधानों के साथ और उनके संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। गोद लेने की पुष्टि करते समय केंद्र सरकार (पहले गवर्नर जनरल) को दो प्रारंभिक तथ्यों पर विचार करना चाहिए, (1) क्या विधवा को दत्तक गृहण की शक्ति है और (2) क्या उसने वास्तव में दिवंगत इस्तिमारदार को एक पुत्र दत्तक लिया है। तीसरे परंतुक में उल्लिखित पुष्टि में आवश्यक रूप से इन दो तथ्यों का निर्धारण शामिल है। इन दो तथ्यों से अलग होने पर पुष्टि का कोई अर्थ नहीं है और कोई समझने योग्य सामग्री नहीं है। इस मामले के तथ्य यह भी स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि धारा 24 के तहत एक नोटिस पर कई दावेदारों ने अपने दावे सामने रखे: विधवा ने फिर अपीलांट नंबर 1 को अपनाया और पुष्टि के लिए एक आवेदन किया गया। इस आवेदन का विरोध किया गया और जांच के बाद, राष्ट्रपति ने दत्तक गृहण की पुष्टि की।

प्रत्यर्थी नंबर 1 ने दत्तक गृहण की पुष्टि करने वाले आदेश पर पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति को आवेदन दिया और फिर उन्हें सूचित किया गया कि राष्ट्रपति को पुष्टि के आदेश को संशोधित करने का कोई कारण नहीं दिखता।

यदि मेरा विचार सही है कि पुष्टिकरण का आदेश दो प्रारंभिक तथ्यों को ध्यान में रखता है, तो धारा 119 यह बिल्कुल स्पष्ट करती है कि कोई भी वाद पुष्टिकरण के आदेश के विपरीत निर्णय प्राप्त करने के लिए नहीं है। धारा 119 के खंड (ए) के तहत पुष्टि के आदेश को शामिल करते हुए जैसा कि मेरे विचार में है, दो प्रारंभिक तथ्यों का निर्धारण कानूनी रूप से और सही ढंग से किया गया माना जाएगा; और खंड (बी) के तहत उस निर्धारण को चुनौती देने के लिए कोई वाद दायर नहीं किया जाएगा। "कानूनी तौर पर" और "सही ढंग से" शब्द महत्वपूर्ण हैं। कानूनी रूप से शब्द का अर्थ है कि आदेश कानून के तहत वैध रूप से किया गया है; 'सही' का अर्थ है कि यह तथ्यात्मक रूप से सही और उचित है।

इसलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न यह है - धारा 23 के तीसरे परंतुक में संदर्भित पुष्टिकरण आदेश में क्या शामिल है? क्या इसमें दो तथ्यों का निर्धारण शामिल है - (1) दत्तक गृहण की शक्ति और (2) दत्तक गृहण का तथ्य? यदि ऐसा होता है और मुझे लगता है कि ऐसा होता है, तो धारा 119 वर्तमान वाद को वर्जित करती है।

मुझे ऐसा लगता है, और मैं इसे बड़े सम्मान के साथ कहता हूं, कि कोई भी अन्य दृष्टिकोण धारा 23 के तीसरे परन्तुक को पूरी तरह से निरर्थक बना देगा। धारा 23 और 24 इस्तिमारारी जागीर के उत्तराधिकार के पूरे क्षेत्र को कवर करते हैं। धारा 24 के तहत, धारा द्वारा प्रदान नहीं किए गए मामले में उत्पन्न होने वाली संपत्ति के उत्तराधिकारी के अधिकार के बारे में कोई भी प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा प्रावधान के अधीन तय किया जाएगा। धारा 24 के तहत केंद्र सरकार की शक्ति निरंकुश है। यदि धारा 23 के तृतीय परन्तुक के तहत किसी विधवा द्वारा दत्तक गृहण की पुष्टि के आदेश के बावजूद कोई वाद दत्तक गृहण को चुनौती देता है, तो क्या होता है जब सिविल कोर्ट दत्तक गृहण को अवैध मानता है? यह माना जाता है कि इस तरह की पुष्टि को चुनौती नहीं दी जा सकती - वह आदेश कायम रहना चाहिए। तो क्या मामला धारा 23 या धारा 24 के अंतर्गत आता है? यदि यह धारा 24 के अंतर्गत आता है, तो उत्तराधिकार के प्रश्न पर फिर से केंद्र सरकार को निर्णय लेना होगा। यदि केंद्र सरकार अपने ही पुष्टिकरण आदेश की अनदेखी नहीं करती है, तो परिणाम, गतिरोध होगा। धारा 23 और 24 को एक साथ पढ़ने पर, मुझे नहीं लगता कि इसका उद्देश्य यह था कि विधवा द्वारा दत्तक गृहण की पुष्टि के आदेश के बावजूद दत्तक को चुनौती देने के लिए एक वाद दायर किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप पुष्टि के प्रभाव को रद्द किया जा सकता है।

न ही मुझे लगता है कि भूम भूमि से संबंधित धारा 33 और 34 उचित हैं। धारा 33 में धारा 23 के तृतीय परन्तुक की तरह कोई प्रावधान नहीं है, जो एक विधवा द्वारा दत्तक गृहण की पुष्टि करता है। पूरे मामले को धारा 33 के तहत छोड़ दिया गया है, और धारा 119 उस धारा के संदर्भ में कोई वर्जन नहीं करती है।

हमारे सामने कुछ तर्क थे कि क्या उन संपत्तियों से संबंधित वाद इस्तिमरारी जागीर का हिस्सा नहीं है। विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश के समक्ष ऐसा कोई विवाद्यक उठाया गया प्रतीत नहीं होता है और जहां तक मैं संशोधित वादपत्र से समझ सकता हूं, यह वाद इस्तिमारारी जागीर और उसकी चल और अचल संपत्तियों से संबंधित है।

इस आशय का एक संवैधानिक बिंदू मुद्दा उठाने का आग्रह करने के लिए एक आवेदन भी था कि यदि धारा 119 का अर्थ इस प्रकार है कि वर्तमान मामले की तरह एक वाद को रोक दिया जाए, तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है । यह बात हमारे सामने नहीं रखी गयी;

इसलिए, इन इस्तिमरारी सम्पदा की प्रकृति और घटनाओं और किए गए वर्गीकरण के कारणों की व्याख्या करना अनावश्यक है। हमारे सामने बहस निर्माण के शुद्ध प्रश्न पर आगे बढ़ी और मैंने स्वयं को केवल उसी प्रश्न पर संबोधित किया है।

पहले से दिए गए कारणों से, मेरा मानना है कि विनियमन की धारा 23 और 119 के उचित निर्माण पर, वर्तमान वाद वर्जित है। तदनुसार, मैं अपील की अनुमति दूंगा और वाद को लागत सहित खारिज कर दूंगा।

आदेश

न्यायालय द्वाराः-न्यायालय के बहुमत के निर्णय के अनुसार, अपील लागत सहित खारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक गौरव शर्मा (न्यायिक अधिकारी) द्वारा किया गया है।

अस्वीकारणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।